

**नाराजगी**

# एनसीओए ने सरकार को सौंपा ज्ञापन पीएसयू के निजीकरण के खिलाफ निकाला आक्रोश मार्च



नई दिल्ली, लोकसत्य

पीएसयू के निजीकरण और उसकी खराब स्थिति के लिये जिम्मेदार सरकारी नीतियों के विरोध में नेशनल कंफेडरेशन ऑफ ऑफिसर्स एसोसिएशन ने प्रदर्शन किया।

इसके लिये एसोसिएशन के पदाधिकारियों व विभिन्न पीएसयू के अधिकारियों ने बड़ी संख्या में एकजुट होकर विरोध प्रकट किया और अपनी

संस्था के अध्यक्ष और एमटीएनएल के अधिकारी वीके तोमर ने बताया कि पीएसयू की भूमिका हमेशा से राष्ट्र के निर्माण में अहम रही है

मांगों पर सरकार को जल्द पहल करने की मांग की। एसोसिएशन ने ईस्टर्न कोर्ट से जंतर-मंतर तक मार्च निकाला फिर सरकार के नाम एक ज्ञापन सौंपा। इस विरोध मार्च को



संसद सदस्यों तपन सेन और सुदीप बंद्योपाध्याय ने भी संबोधित किया और सरकार की उस नीति की आलोचना की जिसके तहत सरकार सार्वजनिक उद्यम की इकाईयों को बेच रही है।

संस्था के अध्यक्ष और एमटीएनएल के अधिकारी वीके तोमर ने बताया कि पीएसयू की भूमिका हमेशा से राष्ट्र के निर्माण में अहम रही है। उन्होंने कहा कि इन इकाईयों के जरिये सरकार को बाजार में प्रतिस्पर्धा बनाने और नीति निर्धारण में मदद

मिलती है। इनके जरिये सरकार ने आर्थिक सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये नीति बनाई और पिछले सात दशकों में देश के आर्थिक विकास में बड़ी भूमिका अदा की।

उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि सरकार सार्वजनिक उद्यमों में निजी निवेश की सीमा आधे से कम रखे। सरकार पीएसयू की तंगहाली की जिम्मेदार अधिकारियों को बताती है जोकि गलत बात है। इसके लिये भी सरकार की ही नीतियां जवाबदेह हैं।

लोकसत्य

दि० - 23.3.2017

# NCOA writes to PMO over stakes in CPSUs

SPECIAL CORRESPONDENT  
NEW DELHI

The National Confederation of Officers' Association has written to the Prime Minister's Office seeking reversal of the government's decision to disinvest in central public sector units, while urging it to revert to earlier policy of retaining majority stakes in all CPSUs.

"The role of CPSUs is in nation building and also in enabling the government to maintain market competitiveness and enforcement of its policy framework," the letter said, pointing out that these firms enable the government to enforce its policies in different sectors and check cartelisation by the private sector.

The executives from public sector enterprises from across the country on Wednesday organised a march from East Court Janpath to Parliament against the move.

## No tangible results

The association pointed out that privatisation and strategic sale of CPSUs have not shown any tangible results in the past in terms of market access or financial inputs from strategic partners or in any manner.

"The government instead should proactively work towards revitalising these CPSUs to enable and empower them to effectively and successfully compete with the private sector," it said.

It added that "such unwarranted ad hoc policy pronouncements" destabilise the units and negatively impact the morale of its employees and officers.

It also said that the government should come out with white paper comprehensively spelling out the future role of CPSUs.

The government is eyeing to raise Rs.20,500 crore from strategic sales of public sector units.

THE HINDU  
Dt - 23.03.2017

CM  
K